IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उच्च शिक्षा में बहु-विषयक उपागम की चुनौतियाँ

[1]Name of 1st Author सोहन सिंह, [2]Name of 2nd Author ज्योति शुक्ला,

[1]Designation of 1st Author शोध छात्र, [2]Designation of 2nd Author शोध छात्रा,

[1]Name of Department of 1st Author शिक्षाशास्त्र विभाग, सी. एम. पी. कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

[1]Name of organization of 1st Author शिक्षाशास्त्र विभाग, सी. एम. पी. कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय city- प्रयागराज, country- भारत

Abstract: **उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहु- विषयक उपागम ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाने में सहायक हैं तथा समाज की अनेक समस्याओं को हल करने में छात्रों को सक्षम बनाता है I सी.बी.सी.एस. ने छात्रो को अपने विषयों को पसंद के विषय विशेषज्ञ से पढने की अनुमति देता है I नई शिक्षा नीति 2020 में भारत सरकार ने बहु – विषयक शिक्षा प्रणाली की ओर ध्यान दिया है I हालाँकि संस्थागत पुनर्गठन की चुनौतियाँ हैं क्योकि भारत में बहुत से सरकारी, गैर-सरकारी तथा प्राइवेट विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व अन्य संस्थान एकल विषय से ही संचलित हो रहें हैं I जिन्हें बहु- विषयक संस्थान में परिवर्तित करने के लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता है I पाठ्यचर्या का पुनर्गठन भारतीय उच्च शिक्षा में बहु- विषयक शिक्षण को आंशिक रूप से सक्षम करता है I नई शिक्षा नीति 2020 एक प्रगतिशील एवं भविष्य उन्मुखी दस्तावेज है जिसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, समग्र और बहु – विषयक बनाना है I यह विद्यार्थियों को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रो के भिन्न- भिन्न पाठ्यक्रमों को सीखने की अनुमति देती है I**

Index Terms - बहु- विषयक उपागम, सी.बी.सी.एस., ओ.ई.सी.डी., समानता, अंतर्विषयक उपागम

I. INTRODUCTION

19वीं और 20वीं सदी में विश्वविद्यालयी शिक्षा का आधार विभिन्न विषयों के सापेक्ष विषयक ज्ञान प्राप्त करना था I 21वीं सदी में ज्ञान की प्रगति को नवीन परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है I समाज की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए हमारे पास विषयों की गतिशील अंतर- क्रियायें होती है I उच्च शिक्षा में बहु – आयामी उपागम एक नयी पद्धति है, जो छात्रो को विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट विषयों के पाठ्यक्रमों का पता लगाने और अध्ययन करने की अनुमति देती है I इसमें शिक्षा किसी विशेष अनुशासनात्मक शिक्षा तक सीमित नहीं हैI कोई भी छात्र एक – साथ कई विषयों का अध्धयन कर सकता है I बहु- विषयक उपागम पाठ्यचर्या एकीकरण का एक तरीका है, जो विविध दृष्टिकोणों को सामने लाता है तथा विभिन्न विषयों से सम्बंधित ज्ञान को अर्जित करने में छात्रों द्वारा उपयोग किया जाता है I1 बहुविषयक उपागम में एक विषय की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक साथ कई विषयों का उपयोग किया जाता है I

बहु-विषयक उपागम शिक्षा के क्षेत्र में एक नयी विधि है जो छात्रो को भिन्न भिन्न क्षेत्रो से विशिष्ट विषयों या पाठ्यक्रम का पता लगाने और उसका अध्ययन करने कि अनुमति देता है I बहु-विषयक उपागम छात्रो को अपने करियर विकल्पों को आकार देने में मदद करता है2 I छात्रो को बहु- विषयक उपागम को अपनाने और सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा छात्र-प्रवेश जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित कर प्रोत्साहित करना आवश्यक है I

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोगात्मक उपागम को महत्त्व दिया गया है जो शिक्षण संस्थानों को बहु-विषयक उपागम पर ध्यान देने के लिए निर्देशित करती है I लेकिन हितधारक अभी भी बहु – विषयक उपागम के फायदे और नुकसान को लेकर असमंजस में है I उदार शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख स्तम्भ है जो इस बात की वकालत करती है कि शिक्षा समग्र और बहु-आयामी होनी चाहिए I यह उपागम शिक्षार्थियों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने और उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक , राजनैतिक, अध्यात्मिक, और संवेगात्मक विकास को प्राप्त करने में मदद करता है I अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए एक अभिनव और लचीले पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमे पर्यावरण शिक्षा , सामुदायिक जुडाव, सेवा तथा मूल्य आधारित शिक्षा के साथ क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाओं को शामिल किया जाना है I3

भारत में उच्च शिक्षा

भारत हमेशा से ही विद्वानों और शोधार्थियों का देश रहा है I प्राचीन काल में भी भारत तक्षशिला, नालंदा ,विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था I भारत में स्वतंत्रता के समय 20 विश्वविद्यालय और लगभग 500 – 600 कॉलेज थे जिनमे लगभग 250,000 छात्र पंजीकृत थे I स्वतंत्रता के उपरान्त भारत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक रूप से प्रगति किया है I ए आई एस एच ई (AISHE) 2019 -20 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1043 विश्वविद्यालय, 42343 कॉलेज ,11779 एकल संस्थान सूची बद्ध है I जिनमे प्राईवेट विश्वविद्यालय 396, ग्रामीण परिवेश में स्थिति विश्वविद्यालय 420 हैं I 17 विश्वविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए कार्यरत हैं I एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय

सहित एक राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय है I 522 सामान्य, 177 तकनीकी, 63 कृषि व सम्बद्ध, 66 चिकित्सा, 23 विधि, 12 संस्कृत, 11 भाषा विश्वविद्यालय तथा 145 अन्य वर्ग के विश्वविद्यालय हैं इनमे केवल 2.7% कॉलेजों में शोधकार्य तथा 35 .04 % कालेजों में परास्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है I4

वर्ष 2019 -20 तक लगभग 38.5 मिलियन छात्र उच्च शिक्षा में पंजीकृत थे I जिनमे से 19.6 मिलियन पुरुष तथा 18.9 मिलियन महिलाएं पंजीकृत हैं I उच्च शिक्षा के लिए सकल पंजीकरण अनुपात (GER) 27.1 है I दूरस्थ शिक्षा के लिए कुल पंजीकृत संख्या का 11.1% है, जिसमे 44.5% महिलाएं हैं तथा लगभग 79.5% छात्र स्नातक स्तर में पंजीकृत हैं वही 2,02550 छात्र यानि कुल पंजीकृत संख्या का मात्र 0.5% छात्र पी. एच. डी. के लिए पंजीकृत है I5

अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में बहु विषयक उपागम

ओ ई सी डी की रिपोर्ट 1972 में कहा गया है कि अंतर – विषयक शैक्षिक प्रणाली की उत्पत्ति संस्कृतिक और बौद्धिक परम्पराओं के द्वारा हुई है I संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए दी जाती है I जबकि यूरोप में बौद्धिक और वैज्ञानिकता के विकास के लिए सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती है I इन दोनों देशों की प्रवृत्तियों में शिक्षण और अनुसंधान में अंतर – विषयक प्रणाली की जरूरतों से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का उत्तर देने तथा अधिक अच्छे ढंग से व्याख्या करने के लिए विकसित किया गया है I ओ ई सी डी 1972 की रिपोर्ट में कई तरीको का पालन किया जाता है I कभी कभी बहु विषयक प्रणाली को संकट के रूप में देखा जाता है जिससे मूल शिक्षण प्रणाली की कठोरता को दूर किया जा सके6 I ओ.ई.सी.डी. की रिपोर्ट में बहु – विषयक प्रणाली के उद्धेश्यों को छात्रों ,शिक्षको ,विभागों और विश्वविद्यालयों के दृष्टि से सूचित करती है I7 यूनाइटेड किंगडम ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहु-विषयक उपागम को कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेस में प्रारंभ करने के लिए समीक्षा की I व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में नये विषयों का समावेश बढ़ रहा है I जैसे इंजीनियरिंग के साथ प्रबंधन ,चिकित्सा के साथ सामाजिक, विदेशी भाषाएँ व कंप्यूटर व अन्य हैं I सैद्धांतिक एकीकरण जैव प्रौद्योगिकी ,संज्ञानात्मक विज्ञान, संचार, संचालन सिस्टम विज्ञान आदि में पाया जाता हैI8 यूरोप में कई बहु विषयक पाठ्यक्रम जोड़ जा रहे है I लिंड, ब्लाम और कोला ने पाया कि शैक्षिक सत्र 2017-18 कि शुरुआत से हेलसिंकी विश्वविद्यालय ने 32 बहु – विषयक स्नातक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है9 I हेलसिकी विश्वविद्यालय उस व्यवस्था का भी समर्थन करता है I जहाँ शिक्षक एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, तथा पारंपरिक मॉडल के बजाय विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक शिक्षक एक विषय को पढाता है I10

भारत में बहु – विषयक उपागम

विश्विद्यालय अनुदान आयोग ने 1963 में दुनिया के विभिन्न देशों और क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओ से सम्बंधित अध्ययन के लिए चयनित विश्वविद्यालयों को सहायता देने का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था जो उन देशों से सम्बंधित था जिनके साथ भारत का सीधा और निकटतम सम्बन्ध थाI11 क्षेत्र अध्ययन केंद्र बहु -विषयक उपागम के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रहें हैं , जैसे स्कूल आफ इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज गोवा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, रक्षा और रणनीतिक अध्ययन के विषयों से सम्बंधित शिक्षणशास्त्र और अनुसंधान को बढाने की दृष्टि से वैश्विक व क्षेत्रीय अध्ययन के बीच में कार्यरत है I केरल विश्वविद्यालय में कनाडाई अध्ययन केंद्र की स्थापना 1991 में भारत – कनाडा संबंधों को आगे बढाने के लिए और कनाडा के अध्ययन में अकादमिक शोध का पता लगाने तथा बढ़ावा देने के लिए की गयी थीI12 यू जी सी ने कनाडा की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2003 में इसे एक प्रतिष्ठित क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र का दर्जा प्रदान किया I इस क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र में संस्कृति, साहित्यिक अध्ययन , समाजशास्त्रीय और जनसांख्यिकी अध्ययन ,विज्ञान और प्रोद्योगिकी ,राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है I भारत में महिलाओं के मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए 1970 के दशक में बहु -विषयक उपागम की झलक देखने को मिलती है जब नारीवादी आन्दोलन और 1977 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त महिलाओं की स्थिति पर एक समिति "समानता की ओर" की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना बम्बई विश्वविद्यालय में की जाती हैI यह रिपोर्ट भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य ,रोजगार ,सामाजिक स्थिति और राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करती है I बाम्बे में महिलाओं पर शोध करने के लिए एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय को एक इकाई के रूप में मान्यता दी गयी जिसे 1985 में एक अधिकारिक रूप से केंद्र बना दिया I बहु विषयक उपागम में महिलाओं पर शोध को बढ़ावा देने के लिए भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषण किया गया जिससे अंतर्गत महिलाओं की स्थिति पर अध्ययन के लिए विभिन्न केन्द्रों की स्थापना की गयी13 I हाल के वर्षों में कई राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने बहु विषयक उपागम के साथ व्यावहारिक पाठ्यक्रम आरम्भ किया है जिससे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि से समाज की समस्याओं को हल करने के लिए बहु विषयक उपागम को अपनाना अनिवार्य हो गया है I

भारत में बहु- विषयक उपागम की चुनौतियाँ

भारत की स्वतंत्रता के 74 वर्ष के बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है I हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में अभी तक सम्मिलित नहीं हो पाया है I यूं जी सी लगातार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बहु -विषयक उपागम पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है I उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण व बहु – विषयक उपागम और अंतर-विषयक उपागम को अपनाने में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कोलेजों के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं –

- उच्च शिक्षा में सकल पंजीकृत अनुपात(NER) 27.1% है जो कि विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है I
- विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य सकल पंजीकरण अनुपात में समानता नहीं है, क्षेत्रीय भिन्नताएं भी हैं, कुछ राज्यों में उच्च पंजीकरण है जब की कुछ राज्य राष्ट्रीय पंजीकरण अनुपात से भी बहुत पीछे है I
- भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में बहु -विषयक उपागम के लिए बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण चुनौती बन रहा है I

- सार्वजानिक क्षेत्र द्वारा चल रहे संस्थानों में बुनियादी और भौतिक सुविधाओं का अभाव है I जिसके कारण नयी शिक्षा नीति 2020 के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतर -विषयक व बहु -विषयक उपागम को अपनाने में समस्या हो रही है I
- उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों व कालेजों में बड़ी संख्या में शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त है, जिसके कारण बहु-विषयक उपागम व गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा छात्रों को उपलब्ध करा पाना एक कठिन कार्य है I
- बहु-विषयक उपागम से सम्बंधित बहुत कम शोध कार्य हमारे देश में किये गये हैं I उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नाम मात्र के विद्वान हैं जिनके लेखन को प्रसिद्ध पाश्चात्य लेखकों ने उद्धृत किया है I बहु-विषयक शोध कार्य के लिए अपर्याप्त संसाधनों व सुविधाओं के साथ-साथ अच्छे विद्वानों की भी कमी है I
- भारत में उच्च शिक्षा में बहु-विषयक उपागम को सुचारू रूप से संचालित करने में भारतीय शिक्षा के प्रबंधन, विकेन्द्रीयकरण नौकरशाही की संरचना व उत्तरदायित्व में पार्दर्शिता और व्यावसायिकता की कमी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है I
- विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों और छात्रों की संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इनके प्रशासनिक कार्यों का बोझ काफी बढ़ गया है जिसके कारण शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान कम हो गया है I

सुझाव

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कारक हैं जो शिक्षा की प्रकृति और उद्देश्य के अभिन्न अंग है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहु-विषयक उपागम के समक्ष समस्या उत्पन्न करते है I इन कारकों में प्रमुख रूप से संगठनात्मक नेतृत्व, शासन सरचना, विविध हितधारक, उच्च शिक्षा के घटक तथा संस्थागत संस्कृति शामिल है I उच्च शिक्षा में बहु-विषयक उपागम के लिए आवश्यक है कि सकल पंजीकरण दर को बढाकर कम से कम 5% तक लाया जाये साथ ही विभिन्न वर्गों के मध्य समानता लाने के लिए कम पंजीकरण दर वाले वाले वर्गों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाये I उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहु-विषयक उपागम के सफलतापूर्वक संचालन के लिए एकल विषयक विश्वविद्यालयो, कालेजों व संस्थानों में नये – नये विभाग व बुनियादी विकास किया जाना आवश्यक है I सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाले तथा प्रबंधकीय क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों के कमजोर बुनियादी ढाचे को बढ़ाना आवश्यक है तथा उच्च शिक्षा में रिक्त विषय विशेषज्ञों के पदों को तत्काल भरकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध व नवाचार में बहु-विषयक उपागम को बढ़ावा देना चाहिए I उच्च शिक्षा से सम्बंधित रिक्त पदों को भरना अतिआवश्यक है जिससे आने वाले समय में शिक्षकों व अन्य कर्मियों की कमीं को दूर जा सके क्योकि आने वाले समय में सकल पंजीकरण दर के बढ़ने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की संभवना है जिससे विश्वविद्यालयों, कालेजों व शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त प्रबंधन, नौकरशाहों, कर्मचारियों व विषय विशेषज्ञों की कमी को समय रहते दूर करना आवश्यक है जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहु-विषयक उपागम को सरल एवम अच्छे तरीके से संचालित किया जा सके I

सन्दर्भ

1. Government of India. (2005). National Knowledge commission Report to the Nation, 2006-2009, published by National Knowledge Commission, New Delhi https://web.archive.org/web/20140123091014/ .
2. Agarwal, P. (2007). Higher education in India: Growth, concerns and change agenda. Higher Education Quarterly, 61(2), 156-167.
3. National Education Policy 2020. Ministry of Human Resource development. Government of India
4. https://www.cemca.org/ckfinder/userfiles/files/EdTech-Notes-Multidisciplinary-Approach-in-Higher-Education.pdf
5. http://aishe.gov.in/aishe/home. AISHE Report 2019-20
6. R, Van der Vaart & A. Heijnen (Ed.), Place of Engagement: Reflections on higher Education in 2040- A Global Approach (pp.75-88). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.1515/9789048543656-011.
7. Krishnaraj, M. (2008). The First Women's studies Research Centre: A History of Women's studies and its progenitors. Indian Journal of Gender Studies, 25(2), 212-233. https://doi.org/10.1177/097152158763472.
8. Lindblom, S.& Kola, J. (2018). The importance of evidence- base development of teaching and learning at university.
9. Kezar, A., & Eckel, P.D. (2003). The effect of institutional culture on change strategies in higher education: Universal principles or culturally responsive concepts? The Journal of Higher Education, 73(4), 435-460.
10. Welsh, J. F., & Metcalf, J. (2003). Faculty and administrative support for institutional effectiveness activities. Journal of Higher Education, 74(4), 445-468.

11. https://www.iferp.in/blog/2020/12/05/multidisciplinary-approach-research-the-benefits-challenges-applicability-in-the-modern-business-landscape/.
12. Dr K. Meenakshi Sundaram (2020), National Education Policy 1986 Vs National Education Policy 2020- A Comparative Study, Special Issue of First International Conference on Advancements in Management, Engineering and Technology (ICAMET 2020), IRJASH, Volume 02 Issue 10S October 2020, e-ISSN 2582-4376
13. NEP 2020: National Research foundation paves a way for self-reliant India. http://www.academics4nation.org